



REGISTRED NO. D—(D) 73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. ३७]

नई विल्सो, शनिवार, सितम्बर १५, १९७९ (भाद्रपद २४, १९०१)

No. 37]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 15, 1979 (BHADRA 24, 1901)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संलग्न दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

पृष्ठ

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर)

भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों विनियमों तथा प्रावेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर)

भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की

गई विधितर नियमों, विनियमों, प्रावेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की

गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

भाग II—खण्ड 1—भैंसिनियम, भ्रष्टादेश और

विनियम

भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रबन्ध समितियों की रिपोर्ट

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ गज्ज लेव्हरों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राविकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और

पृष्ठ

जारी किए ए साक्षात्रण नियम (जिसमें साधारण प्रकार के प्रावेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

पृष्ठ

2175

531

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राष्ट्र लेव्हरों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राविकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं

2579

1149

भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिकारियों विधित विधिक नियम और आदेश

339

39

भाग III—खण्ड 1—भैंसिनियम, संघ लोक सेवा आयोग, रेस प्रशासन, उच्च अधिकारियों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

7075

817

भाग III—खण्ड 2—एकस्त कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस

541

—

भाग III—खण्ड 3—मुख्य प्रायुक्तों द्वारा या उनके प्राविकार से जारी की गई अधिसूचनाएं

105

—

भाग III—खण्ड 4—विधिक नियमों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस सम्मिलित हैं

2177

—

भाग IV—गैर सरकारी अधिकारियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस

119

531

CONTENTS

	PAGE		PAGE
PART I SECTION 1.—Notification relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	531	(other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2175
PART I SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1149	PART II SECTION 3.—Sub. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2579
PART I SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	39	PART II SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	339
PART I SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	817	PART III SECTION 1.—Notification issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	7075
PART II SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations.	—	PART III SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	541
PART II SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—	PART III SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	105
PART II SECTION 3.—Sub. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India	—	PART III SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2177
		PART IV —Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	119

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त मंत्रालय
(राजरव विभाग)
नई विल्ली, दिनांक 23 अगस्त 1979
संकल्प

सं० ए०-११०१२/१८१/७७-प्र० ४—दिनांक २८-९-१९७८ के संकल्प सं० ए० ११०१३/१८१/७७-प्र०-४ के वैराग्राफ ४ तथा संकल्प दिनांक २६ मार्च १९७९ में निहित आदेशों में शांकिक संशोधन करते हुए, भारत सरकार ने नियम किया है कि 'वीनी पर केन्द्रीय उत्तराधिन शुल्क में कूट देने संबंधी योजना (युपरीक्षण) समिति' प्रधानी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) को विसम्बार १९७९ के प्रत्यक्ष तक पेश करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक एक प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए और इसे सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

रवि दत्त शर्मा, अवर सचिव

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(पेट्रोलियम विभाग)
नई विल्ली, दिनांक 22 अगस्त 1979
आदेश

विषय:—बी०-५५ संरक्षन (अपतटीय क्षेत्र) २६३.५० वर्ग किलोमीटर
क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति।

सं० १२०१२/४/७९—प्रोडक्शन:—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, १९५९ के नियम ५ के उपनियम (१) की धारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस प्रायोग, तेल भवन, लेहराहन (जिसको आदि में प्रायोग कहा जायेगा) बी-५५ संरक्षन (अपतटीय) क्षेत्र में २६३.५० वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम भिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस ८-१०-१९७८ से एक वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है। इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिये गये हैं।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है:—

- (क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा।
- (ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई अनिज पदार्थ पाए गए पूर्ण अवैरो के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।
- (ग) स्वतं शुल्क (रायलटी) निम्नलिखित दरों पर ली जायेगी:
 - (i) समस्त अशोधित तेल तथा कैमिंग हैंड कंडेस्ट पर ४२/-
६० प्रति भीट्रिक टन या ऐसी दर जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।
 - (ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित वर के अनुमार होगी।
 - (iii) स्वतं शुल्क (रायलटी) की अवायगी, पेट्रोलियम मंत्रालय, नई विल्ली के बेतन तथा लेखा अधिकारी को दी जायेगी।

(घ) प्रायोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम ३० दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, कैमिंग हैंड कंडेस्ट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शनी बाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिये गये प्रपत्र में भरकर बेना होगा।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, १९५९ की आवश्यकता के अनुसार आयोग ६०००/- रुपये की धनराशि प्रतिशूलि के रूप में जमा करेगा।

(च) प्रायोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संरक्षना प्रत्येक वर्ष किलोमीटर या उसके किसी अन्य जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी।

१. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए	4 रुपये
२. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए	20 रुपये
३. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए	100 रुपये
४. लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए	200 रुपये ; और
५. लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम वर्ष	300 रुपये।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, १९५९ के नियम ११ के उपनियम (३) की आवश्यकतानुसार आयोग को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता सरकार को वो माह के नोटिस के बाद होगी।

(ज) केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अन्वेषण के अन्वर्गत पाये गये समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवृत्तानिक आकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः भारीने में निश्चिन्त रूप से केन्द्रीय सरकार को अन्वेषण परिचालनाओं व्यधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा।

(झ) आयोग समुद्र की तनहुंटी और/या उपके धरातल पर आग लगने संबंधी निवारक उपायों की अवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण, मामान तथा साधन बनाये रखा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुश्किल देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा।

(अ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबन्ध लागू होंगे।

(इ) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में प्रायोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक जैसा दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए अवधारणा होगा।

अनुसूची "क"

इस पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के अन्तर्गत बी-55 संख्या (अप-सटीय क्षेत्र) प्राप्ता है और जो अक्षांश $19^{\circ} 30' \text{ उक्तिश } 19^{\circ} 43' 16''$ उत्तर तथा वैशान्तर $71^{\circ} 50' \text{ पश्चिम } 72^{\circ} 3' 10''$ पूर्व के बीच है और मानचित में किनारे के प्लाईटों प्रथमांश, बी, सी, डी और ई को मिलाते हुए चिह्नित किया है तथा इसका क्षेत्रफल 263.50 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्र जहां पर स्थित है उनके प्लाईट जिन अक्षांश और वैशान्तरों पर पड़ते हैं तथा उनके बीच की दूरी निम्नलिखित है :—

अनुसूची "ख"

अशोधित तेल, कोसिंग हैड कंडेसेन्ट तथा प्राकृतिक गैंग के उत्पादन तथा उपके मूल्य सहित मासिक वितरण।

बी-55 संख्या के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस

क्षेत्रफल 263.50 वर्ग किलो मीटर

माह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लीटरों अपरिहार्य रूप से खोये अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा की संख्या प्राकृतिक जलाशय को अनुमोदित पेट्रोलियम सौटाये किलो लीटरों की संख्या प्राकृतिक गैस तथा प्रयोग कार्य हेतु प्रयोग की संख्या

कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त किलो लीटरों की संख्या

टिप्पणी

1

2

3

4

5

ख—कोसिंग हैड कंडेसेन्ट

प्राप्त किये गये कुल अपरिहार्य रूप से खोये अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा की संख्या प्राकृतिक जलाशय को नौटाये अनुमोदित पेट्रोलियम किलो लीटरों की संख्या प्राकृतिक गैस कार्य हेतु प्रयोग किये गये किलो लीटरों की संख्या

कालम 2 और 3 घटाकर प्राप्त किलो लीटरों की संख्या

टिप्पणी

1

2

3

4

5

ग—प्राकृतिक

कुल प्राप्त धन मीटरों अपरिहार्य रूप से खोये अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा की संख्या प्राकृतिक जलाशय को अनुमोदित पेट्रोलियम सौटाये गये धन मीटरों की संख्या प्राकृतिक गैस कार्य हेतु प्रयोग किये गये धन मीटरों की संख्या

कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त धनमीटरों की संख्या

टिप्पणी

1

2

3

4

5

एतद्वारा मैं थी— सत्य निष्ठापुर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूँ कि इस वितरण में दी गयी सूचना पूर्णरूपेण सत्य और सही है उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठ से यह घोषणा करता हूँ।

हस्ताक्षर—

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली-110029, दिनांक 16 अगस्त 1979
संकल्प

सं० एफ० 20019/1/7-प्रश्ना० I—विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष पद से डा० आर्पा राम द्वारा विए गए स्थानपत्र को स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 7 अगस्त 1979 से स्थाई प्रबन्ध किए जाने तक योजना आयोग के सदस्य श्री बी० जी० राजाध्यक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष के बत्तमान कार्यों को विदेश।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, सभी शासित प्रदेशों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, योजना आयोग, रेलवे बोर्ड, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधानमंत्री के कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय और एन० सी० एस० टी० के सभी सदस्यों को संप्रेषित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य जानकारी के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस० बैंकटेश, संयुक्त सचिव

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, विनांक अगस्त 1979

संकल्प

सं० एफ० 14025/1/77-अर्थ नीति—विनांक 6 फरवरी 1978 के संकल्प सं० 14025/1/77-अर्थ नीति के द्वारा पुनर्गठित कृषि मूल्य आयोग को सलाह देने वाले कृषिकों के पेनल में यह निर्णय लिया गया है। दरमदीम पश्चिमी मिक्किम के श्री जे० डी० पालजोर के स्थान पर जिनका उल्लेख क्रम सं० 18 (मिक्किम) पर किया गया है श्री एफ० डी० राय तुरक दक्षिणी मिक्किम को नामजद किया जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, समस्त राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों, योजना आयोग, प्रधान मंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय, लोक सभा मन्त्रिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत महा नियन्त्रक तथा लेखा परीक्षक और कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय और कृषि विभाग के समस्त संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य जानकारी के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस० एस० स्कॉमीनाथन, सचिव

नई विल्ली, विनांक 23 अगस्त 1979

सं० एफ० 4-3/79-एफ०-2—राष्ट्रपति अन्वयन एवं निकोबार द्वीप-ममूळ कारेस्ट एण्ड प्लान्टेशन डबलपरमेंट कारपोरेशन निमिटेड की संगम की नियमावली के अनुच्छेद 67(3) के अनुसार कृषि विभाग के मुख्य लेखा नियन्त्रक श्री बी० आर० रामामूर्ति को श्री वैद्यानाथन के स्थान पर अन्वयन एवं निकोबार द्वीपसमूह फारेस्ट एण्ड प्लान्टेशन डबलपरमेंट कारपोरेशन के निवेशक मण्डल में अंश कालिक आधार पर सरकारी निवेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

जी० नाथक, अवर सचिव

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, विनांक 21 अगस्त 1979

संकल्प

नौवहन

सं० एम डम्बू०/एमएमडी (58)/78-एमडी—भारत सरकार ने इस मंत्रालय के संकल्प संख्या एम० एस० डी०-57/78-एम डी० विनांक 30 फरवरी 1979 के द्वारा गठित उच्चतरीय समिति के कार्यकाल को नौवहन उत्थान में वर्तमान संकट को दृष्टि में रखते हुए भारतीय नौवहन की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए छह महीने की ओर अवधि के लिए 31 जनवरी 1980 तक के लिए बढ़ाने का निर्णय किया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में भाग I खण्ड 1 में प्रकाशित किया जाए।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी नगरों/विभागों/प्रमुखतरीय राज्य सरकारों/संघ धेर के प्रशासकों और अन्य संबंधित क्षेत्रों को भेजी जाए।

श्रीमती मन्मानी निर्मल, अवर सचिव

ऊर्जा मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

नई विल्ली, विनांक 20 अगस्त 1979

संकल्प

सं० 2/10/79-य० एस० डी० IV (.)—पूर्वी क्षेत्रीय विजली बोर्ड में विभिन्न राज्य की प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से उक्त बोर्ड के गठन संबंधी मंत्रिलय में संशोधन करने का निर्णय किया गया है। इस निर्णय के अनुसारण में संकल्प सं० विजली-दो-34 (10)/77 विनांक 12 जुलाई 1977 द्वारा यथा संशोधित पूर्वी क्षेत्रीय विजली बोर्ड के गठन संबंधी संकल्प सं० ई० एल०-वो०-35(7)/63 विनांक 6 मार्च 1964 के पैरा 2 का पुनर्गठन नीचे लिखे अनुसार किया जाएगा—

1. अध्यक्ष, विहार राज्य विजली बोर्ड।

2. अध्यक्ष, वामोदर धाटी निगम।

3. अध्यक्ष, उड़ीसा राज्य विजली बोर्ड।

4. अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल राज्य विजली बोर्ड।

5. 6 एक प्रतिनिधि यथा कोई ही जो पश्चिम बंगाल और विहार और उड़ीसा की सरकारों में से प्रत्येक के द्वारा समय-समय पर नामित किया गया हो।

8. प्रबन्ध निवेशक, दुर्गापुर प्रोजेक्टन निमिटेड।

9. अपर मुख्य इंजीनियर विद्युत विभाग और विभिन्न सरकार।

10. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि।

11. सदस्य-नियम।

ऊपर (1) से (4) तक में लिखित सदस्य बारी-बारी से एक-एक वर्ष के निए इस क्षेत्रीय विजली बोर्ड के अध्यक्ष होंगे।

यह संकल्प 13 जुलाई 1979 के गम संबंधी संकल्प को अधिकान्त करता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त मंत्रिलय पश्चिम बंगाल, विहार, मिक्किम और उड़ीसा की सरकारों और राज्य विजली बोर्डों को, वामोदर धाटी निगम को, दुर्गापुर प्रोजेक्टन निमिटेड को, पूर्वी-क्षेत्रीय विजली बोर्ड को, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को, भारत सरकार के मंत्रालयों को, प्रधान मंत्री के कार्यालय को, राष्ट्रपति के सचिव को, योजना आयोग की ओर भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक को सूचित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस० रमेश, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 23rd August 1979

RESOLUTION

F. No. A.11013/181/77-Ad.IV.—In partial modification of the orders contained in para 4 of the Resolution No. A.11013/181/77-Ad.IV dated 28.9.1978, and Resolution No. A.11013/191/77-Ad.IV dated 26.3.1979, the Government of India have decided that 'Central Excise Sugar Rebate Scheme (Review) Committee' will submit its report to the Ministry of Finance (Department of Revenue) by the end of December, 1979.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

R. D. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS &
FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF PETROLEUM)

New Delhi, the 22th August 1979

ORDER

Subject : Grant of Petroleum Exploration Licence for B-55 Structure (off-shore) area measuring 263.50 Sq Kms.

No. 12012/4/79-Prod.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil & Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (hereinafter referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to prospect for Petroleum for one year from 8.10.1978 in the B-55 Structure (off-shore) area measuring 263.50 Sq. Kms. the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The Grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below.

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum

(b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged.

(i) Rs. 42/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Department of Petroleum, New Delhi.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 6000/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometre or party thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 20/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 100/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 200/- for the fourth year of the licence;

(v) Rs. 300/- for the first and second year of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month's notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of rule 11 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to the Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration Licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum exploration licence in the form applicable to off-shore areas as approved by the Central Government.

SCHEDULE 'A'

The area covered by this Petroleum Exploration licence falls in B-55 structure (offshore area) and lies between latitudes $19^{\circ} 30'$ South to $19^{\circ} 43' 16''$ North and longitudes $71^{\circ} 50'$ West to $72^{\circ} 3' 10''$ East and is delineated on the map by the line joining the corner points at ABCD and E and measures 263.50 Sq. Kms. area. The latitudes and longitudes on which the points covering the area fall and the distance in between them are as follows :—

	Bearing Lat ⁱ			Long ⁱ		
	Deg	Min	Sec.	Deg	Min	Sec.
Point 'A' is at	19	30		71	50	
Point 'B' is at	19	35	28	71	50	
Point 'C' is at	19	43	16	71	59	
Point 'D' is at	19	43	16	72	3	10
Point 'E' is at	19	30	—	72	0	19

Approximate distance of farthest point from three prominent places on land as follows :—

1. Bombay 115 Kms.
2. Mahin 80 Kms.
3. Dehanu 90 Kms.

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof.

Petroleum Exploration Licence for

B-55 Structure

Area

Measuring 263.50 Sq. Kms.

Month and Year

A-Crude Oil

Total No. of Kilolitres obtained.	No. of Kilolitres unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Kilolitres used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Kilolitres obtained less columns 2 and 3	REMARKS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

B-Casing head condensate

Total number of Kilolitres obtained	No. of Kilolitres unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Kilolitres used for purposes of petroleum exploration approved by Central Government	No. of Kilolitres obtained less columns 2 and 3	REMARKS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

C-Natural Gas

Total number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of Cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	REMARKS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

I, Shri..... do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

By order and in the name of the President of India.

S. M. Y. NADEEM, Under Secy.

DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY

New Delhi-110029, the 16th August 1979

RESOLUTION

No. F. 20019/1/77-Admn.I.—Consequent on the acceptance of the resignation by Dr. Atma Ram of the Chairmanship of the National Committee on Science and Technology, the Government of India have decided that with effect from 7th August, 1979, Shri V. G. Rajadhyaksha, Member, Planning Commission, will look after the current duties of the Chairman, National Committee on Science and Technology, until permanent arrangements are made.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administration of the Union Territories, Ministries/Departments of the Government of India, Planning Commission, Railway Board, President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat and all the Members of the NCST.

Ordered also that Resolution be Published in the Gazette of India for general information.

S. VENKATESH Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, dated 24th August 1979

RESOLUTION

No. F.14025/1/77-Econ.Py.—In the Panel of Farmers to advise the Agricultural Prices Commission, reconstituted *vide* Resolution No. 14025/1/77-Econ. Py. dated 6th February, 1978, it has been decided to nominate Shri L. D. Ral, Tutuk, South Sikkim *vice* Shri J. D. Palzor, Daramdlim West, Sikkim, mentioned at S. No. 18 (Sikkim).

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries and Departments of the Govt. of India, State Govts. and Union Territories Administrations, Planning Commission, Prime Minister's Office, President's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, and all Attached and Subordinate Offices of the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture).

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. S. SWAMINATHAN, Secy.

New Delhi, the 23rd August 1979

No. F.4-3/79-F.II.—In pursuance of Article 67(3) of the Articles of Association of the Andaman and Nicobar Islands Forest and Plantation Development Corporation, Ltd., the President is pleased to appoint Shri V. R. Ramamurthi, Chief Controller of Accounts, in the Department of Agriculture as part-time Government Director on the Board of Directors of Andaman and Nicobar Islands Forest and Plantation Development Corporation Ltd. *vice* Shri U. Vaidyanathan.

G. NAIK, Under Secy.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

TRANSPORT WING

New Delhi, the 21st August 1979

RESOLUTION

SHIPPING

No. SW/MSD(57)/78-MD.—The Government of India decided to extend the term of the High Level Committee set up vide this Ministry's Resolution No. MSD-57/78-MD, dated 30 April, 1979 to examine the problems of Indian shipping in the context of the present crisis in shipping industry for a further period of six months upto 31 January, 1980.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India Part I Section 1.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India/Maritime State Governments/Administrations of Union Territories and all other concerned.

Smt. B. NIRMAL, Under Secy.

MINISTRY OF ENERGY

DEPARTMENT OF POWER

New Delhi, the 20th August 1979

RESOLUTION

No. 2/10/79-USD-IV(.—With a view to give representation to the State of Sikkim on the Eastern Regional Electricity Board (EREB), it has been decided to amend the Resolution relating to the constitution of the Board. In pursuance thereto, para 2 of the Resolution No. EL.II35(7)/63, dated 6th March 1964 relating to the composition of the EREB as amended vide Resolution No. EL.II-34/10/77, dated 12th July 1977 shall be re-constituted as follows :—

1. The Chairman, Bihar State Electricity Board.
2. The Chairman, Damodar Valley Corporation.
3. The Chairman, Orissa State Electricity Board.
4. The Chairman, West Bengal State Electricity Board.
5. 6. 7. A representative, if any, that may be nominated by each of the Government of West Bengal, Bihar and Orissa, from time to time.
8. Managing Director, Durgapur Projects Ltd.
9. Additional Chief Engineer, Department of Power, Govt. of Sikkim.
10. A representative of the Central Electricity Authority.
11. The Member Secretary.

The Members at (1) to (4) above shall be the Chairman of the Regional Electricity Board, by rotation, for one year each.

This resolution supersedes the resolution of even number dated the 13th July 1979.

ORDER

Ordered that the above Resolution be communicated to the Governments and State Electricity Boards of West Bengal, Bihar, Sikkim and Orissa, the Damodar Valley Corporation, the Durgapur Projects Limited, the Eastern Regional Electricity Board, the Central Electricity Authority, the Ministries of the Government of India, Prime Ministers' Office, the Secretary to the President, the Planning Commission and to the Comptroller and Auditor General of India.

Ordered also, that the Resolution be published in the Gazette of India.

S. RAMESH, Jt. Secy.